Socio - economic
condition

haves have nots

वास्तविक गरीबी

Real Poverty

↓

क्षमताओं का अभाव गरीबी है

Note :

(i) तेंदुलकर विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर भारत में उपर्युक्त दृष्टिकोण के अन्तर्गत ऊर्जा के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के न्यूनतम स्तरों से जुड़े खर्चों को भी ध्यान में रखा जाता है।

2400

2100

(ii) लकड़ावाला समिति की सिफारिशों पर भारत में राज्य-विशिष्ट (State specific) गरीबी की रेखाओं की गणना भी की जाती है। ये गरीबी की रेखायें अखिल भारतीय गरीबी के रेखाओं से ऊपर

या नीचे हो सकती है। इसका
एक कारण यह है कि राज्यों
में पारस्परिक रूप से कीमतों
में अन्तर हो सकते हैं।
(UPSC PT)

₹ 816 ₹ 1,000

- बिहार
  - ग्रामीण
  - शहरी
- उत्तर प्रदेश
  - ग्रामीण
  - शहरी

[illegible]

(i) प्रस्तावना -

इसका विकास नीति आयोग द्वारा नवम्बर, २०21 में किया गया।

इसके अन्तर्गत नीति आयोग NMPI (National Multi-dimensional Poverty Index) का निर्माण करता है।

नीति आयोग का NMPI, GMPI से प्रेरित है।

राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

Global MPI

(ii) NMPI में प्रयुक्त होने वाले मानक –

Diagram

NMPI

Education

(i) Years of Schooling

(ii) School-attendance

Health

(iii) Nutrition

(iv) Child & Adolescent Mortality

(V) Maternal Health

Living Standa

(vi) Electrici

(vii) Drinking

(viii) Sanitat

(ix) Cooking

(X) Housin

(Xi) Assets

(Xii) Bank

National

Family

Health

Survey

Year	Rural	Urban	India
2015-16	32.59	8.65	24.85
2019-21	19.28	5.27	14.96

Note – 2015-16 के आँकड़े NFHS-4 पर आधारित हैं जबकि 2019-21 के आँकड़े NFHS-5 पर आधारित हैं।

ट्रिकल-डाउन (Trickle-Down)
और
गरीबी

ट्रिकल डाउन में सरकार द्वारा तीव्र औद्योगीकीकरण को बढ़ावा देकर अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी को दूर करने की कोशिश की जाती है। इसे निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है –

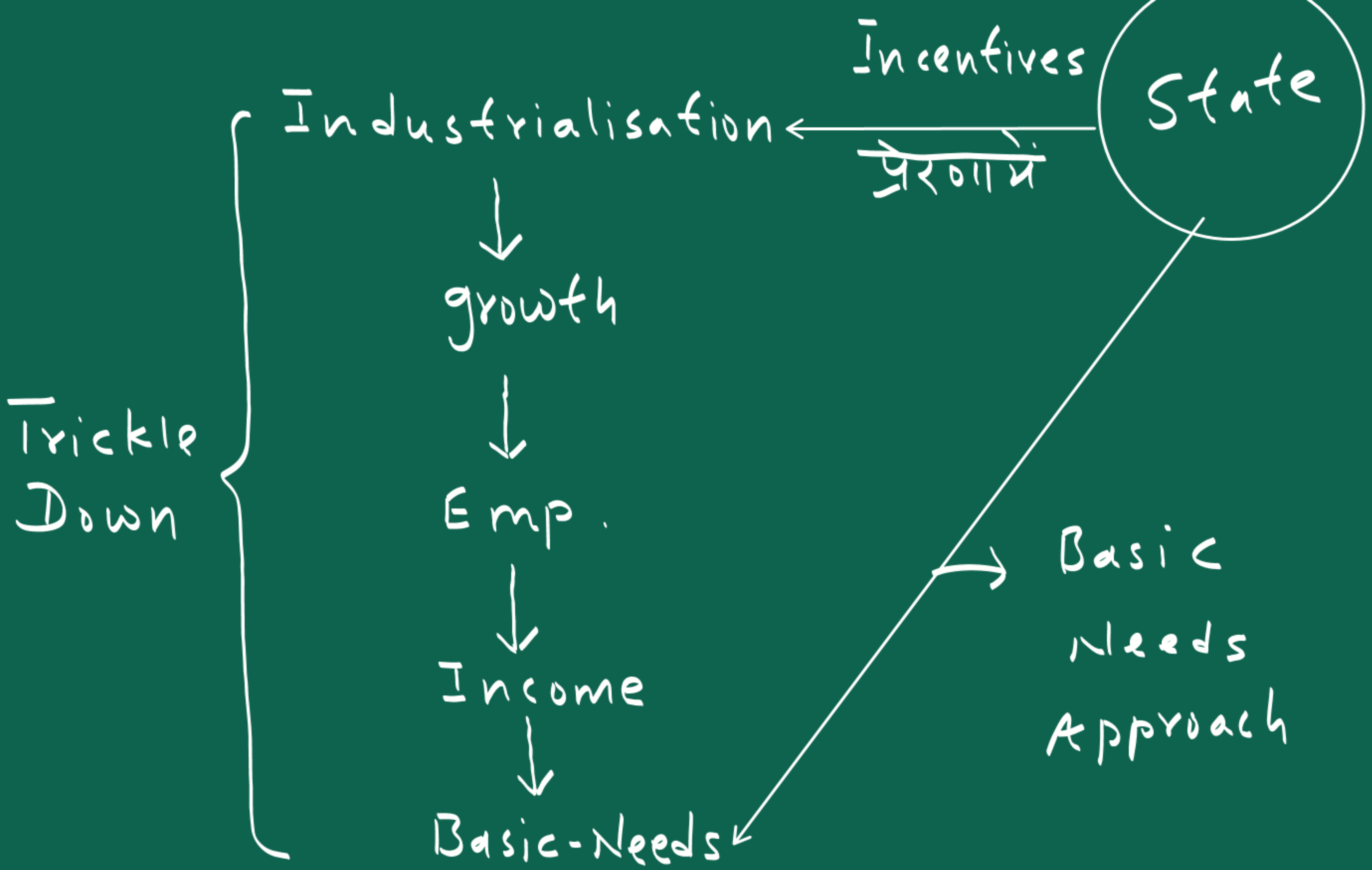

Incentives
State
Industrialisation
प्रेरणायें
growth
Trickle Down
Emp.
Income
Basic-Needs
Basic Needs Approach

1. रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन –

इसके लिए निम्न तीन आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है –

(a) विनिर्माण (Manufacturing)

(b) निर्माण (Construction)

(c) श्रम गहन सेवायें (labour-intensive services)

२. कृषि उत्पादकता को बढ़ाना -

(i) भूमि-सुधारों को लागू करना।

(ii) कृषि विपणन प्रणाली में सुधार करना।

(iii) विस्तार सेवाओं को मजबूत करना।

(iv) कीमत समर्थन प्रणाली में सुधार करना।

(v) नई तकनीकि को लागू करना। आदि।

3. मूलभूत सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाना।

↓

Basic Services
- → चिकित्सा।
- → प्राथमिक शिक्षा।
- → पेयजल।
- → पोषण आदि।

- सामाजिक क्षेत्र की सहभागिता।
- निजी क्षेत्र की सहभागिता।
- IT का प्रयोग। आदि।

इस प्रकार, भारत में गरीबी को कम करने की एक प्रभावी रणनीति का निर्माण किया जा सकता है।

विषमताएं बढ़ रही है।

अब यह कहा जा रहा है कि भारत में Trickle-up या Bottom-up दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

इसके अलावा, Basic Needs approach to development को भी लागू किया जा सकता है।

प्रति व्यक्ति मासिक खर्च